



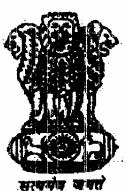
**Latest
Laws.com**

Helping Good People Do Good Things

Bare Acts & Rules

Free Downloadable Formats

Hello Good People !



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 102

8 फालगुन 1927 शकाब्द
राँची, सोमवार 27 फरवरी, 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

27 फरवरी, 2006

संख्या-एल०जी०-०६/२००१-३३/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 [झारखण्ड अधिनियम ०८, २००६]

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें (56वें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
(3) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-6 के द्वितीय पंक्ति में अंकित शब्द समूह “हकदार होगा” के पश्चात् निम्न शब्द समूह जोड़े जायेंगे—

“हवाई यात्रा एवं जल पोत से यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी” ।

3. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-7 का संशोधन--उक्त अधिनियम की धारा-7 में शब्द क्षेत्रीय भत्ता “प्रतिमाह” के बाद अंक “4000/-” के स्थान पर अंक “8000/-” एवं प्रकोष्ठ के अन्दर के शब्द “चार हजार” के स्थान पर शब्द “आठ हजार” प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-8 का संशोधन--उक्त अधिनियम की धारा-8 के खंड (I) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा

“मुख्य मंत्री 11000/- (ग्यारह हजार) रुपये प्रतिमाह, मंत्री 8000/- (आठ हजार) रुपये प्रतिमाह एवं राज्य मंत्री 8000/- (आठ हजार) रुपये प्रतिमाह” ।

5. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-8 का संशोधन--उक्त अधिनियम की धारा-9 में चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह के पश्चात् अंक एवं शब्द अंकित शब्द समूह “रुपये 2000/- (दो हजार रुपये)” के स्थान पर शब्द समूह “रुपये 3000/- (तीन हजार रुपये)” प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राम बिलाश गुप्ता,
सरकार के सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, रौची ।